

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

प्रेस सार

2016 कीलेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 35

एनटीपीसी लिमिटेड के कोयला आधारित
विद्युत स्टेशनों में ईंधन प्रबंधन

प्रस्तावना

कोयला आधारित विद्युत उत्पादन देश की कुल उत्पादन क्षमता का 60.69 प्रतिशत है (31 अक्टूबर 2016)। एनटीपीसी लिमिटेड देश में सबसे बड़ा विद्युत संसाधन है, जिसकी कोयला आधारित क्षमता 40084 मेगावाट है (अक्टूबर 2016)। कोयले की लागत कोयला आधारित विद्युत स्टेशन के कुल उत्पादन टैरिफ का 60 से 70 प्रतिशत है और उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की लागत पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ईंधन प्रबंधन में अक्षमताओं से स्टेशनों के ऊर्जा प्रभार बढ़ेंगे और अंतिम उपभोक्ता के लिए विद्युत की लागत बढ़ जाएगी।

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

स्वदेशी कोयले की खरीद

- 2010-11 से 2015-16 की अवधि के दौरान, विद्युत स्टेशनों ने सीआईएल द्वारा अधिसूचित दरों की तुलना में उच्चतर लागत पर कोयले की खरीद के कारण अतिरिक्त व्यय वहन किया। स्टेशनों ने अधिसूचित दरों पर पहले से ही सहमत कोयले की संविदागत मात्रा हेतु निष्पादन प्रोत्साहन का भुगतान किया। प्रोत्साहन का भुगतान मानी गई सुपुर्द मात्रा (आयातित कोयलाजोवास्तव में स्टेशन पर सुपुर्द नहीं किया गया) पर भी किया गया। कोयले की कमी को पूरा करने के लिए, स्टेशनों को ई-नीलामी और एमओयू के माध्यम से कोयला खरीदना पड़ा जिसके लिए उन्हें प्रीमियम का भुगतान करना पड़ा। इस अवधि के दौरान कोयले की खरीद पर विद्युत स्टेशनों द्वारा ₹ 6869.95 करोड़ का अतिरिक्त व्यय देखा गया।

कोयले का आयात

- एनटीपीसी ने कोयला आयात करने के लिए कोई विशिष्ट नीति लागू नहीं की। विस्तृत नीति के अभाव में, लिए गए मुख्य निर्णयों के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण देखे गये। भागीदारी स्तर में बढ़ोतरी करने के लिए, यद्यपि विभाजन प्रक्रिया शुरू की गई थी, तथापि विभाजन अनुपात को बाद में संशोधित कर दिया गया था, जिससे एल 1 बोलीकर्ता को अधिक मात्रा प्रदान की गई।

कोयले की गुणवत्ता तथा मात्रा का निर्धारण

- कोयले की गुणवत्ता उसके सकल केलोरिफिक मान (जीसीवी) द्वारा निर्देशित की जाती है। कोयले की लागत जीसीवी के समक्रमानुपाती होती है तथा कोयला आधारित विद्युत का मूल्य जीसीवी के व्युत्क्रमानुपाती है। अतः, जितना जीसीवी उच्चतर होगा, उतनी कोयले की लागत उच्चतर होगी तथा विद्युत की लागत कमतर होगी। कोयला कम्पनियों और विद्युत स्टेशनो द्वारा अलग-अलग प्रक्रियाओं के द्वारा जीसीवी मापा जाता है। कोयला कम्पनियों द्वारा प्रयोग की गई प्रक्रिया जीसीवी का उच्चतर मूल्य देती है जिससे कोयले की लागत उच्चतर होजाती है। विद्युत स्टेशन जीसीवी मापने के लिए एक अलग प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं जो कोयले की समान गुणवत्ता के लिए कमतर मूल्य देती है। इससे विद्युत की लागत अधिक हो जाती है जिससे उपभोक्ताओं पर अधिक भार पड़ता है।
- लेखापरीक्षा ने कोयला खानों पर 'एज बिल्ड' जीसीवी, विद्युत स्टेशन के अनलोडिंग केन्द्र पर 'एज रिसीव्ड' जीसीवी तथा एक वर्ष (अक्टूबर/नवम्बर 2012 से सितम्बर 2013 तक) के लिए बॉयलरों में 'एज फायर्ड' जीसीवी की तुलना की तथा यह पाया गया कि 'एज बिल्ड' चरण से 'एज फायर्ड' चरण तक कोयले का जीसीवी कमहोता चला गया तथापि, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, तीनों जीसीवी मूल्य लगभग समान होने चाहिए। एक वर्ष की अवधि के लिये 'एज रिसीव्ड' और 'एज फायर्ड' चरण को ध्यान में रखते हुये प्रति यूनिट विद्युत ऊर्जा प्रभारों में विभिन्न स्टेशनों में ₹ 0.03 से ₹ 0.96 का अंतर था।
- ईंधन आपूर्ति करारों(एफएसए) के अनुसार, विद्युत स्टेशनो को भुगतान कोयला खान के सुपुर्दगी/लोडिंग बिन्दु पर किए गए वजन के अनुसार करना था। एफएसएज में लोडिंग बिन्दुओं पर तुलासेतु के पुनः केलिब्रेशन हेतु अनलोडिंग बिन्दुओं (विद्युत स्टेशन) पर भी तौल करने की सुविधा दी गई थी। हालांकि, स्टेशनों ने स्वदेशी कोयले की नियमित तुलाई नहीं की, जबकि स्टेशनों पर चलायमान तुलासेतु लगाए गए थे। इस कारण स्टेशनों ने प्राप्त कोयले की मात्रा का प्रति सत्यापन करने तथा परिणामी मार्गस्थ हानि की गणना करनेका अवसर खो दिया।

कोयला आपूर्ति प्रबंधन

- 2012-13 के दौरान छः महीने से अधिक तक सात स्टेशनों पर भंडारण स्तर की अति चिंताजनक स्थिति थी (चार दिन की आवश्यकता से कम स्टॉक) तथा 2013-14 के दौरान चार स्टेशनों पर भी ऐसी ही स्थिति थी। 2014-15 में कुछ सुधार हुआ था परंतु तीन स्टेशनों पर भंडारण स्तर की अति चिंताजनक स्थिति बताई गई। इसके अतिरिक्त 2012-13 से 2014-15 के दौरान विभिन्न स्टेशनों पर स्वदेशी कोयला

स्टाक **शून्य स्तर** तक गिर गया था। 2010-11 से 2015-16 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा में कवर किये गये 13 स्टेशनों में से 11 में ₹ 4299.80 करोड़ की संभावित राजस्व हानि के साथ बिजली की 19546.26 मिलीयन यूनिटों की उत्पादन हानि सूचित की गई जो कि इकाईयों को प्रचालन से बाहर करने तथा कोयले की कमी के चलते आंशिक लोड पर परिचालित किये जाने के कारण हुई थी।

- स्टेशनों द्वारा जारी किये गये 'स्थानीय प्रबंधन निर्देशों' के अनुसार, आयातित कोयला यार्ड में पहचाने गये स्थान पर अलग से रखा जाना था।लेखापरीक्षा मेंकोयला स्ट्राक की भौतिक सत्यापन रिपोर्टों(अप्रैल 2010 से मार्च 2016)की समीक्षा की गई और यह पाया गया किआयातित तथा स्वदेशी कोयला एक ही यार्ड में रखा गया था। चिन्हित क्षमता के अतिरेक में आयातित कोयले की उपलब्धता 6 से 158 प्रतिशत के बीच थी जिससे प्रतीत होता है कि वास्तविकसम्मिश्रण से पहले ही स्वदेशी तथा आयातित कोयला यार्ड मेंही आपस में मिश्रित होरहे थे।आयातित कोयले की लागत और गुणवत्ता स्वदेशी कोयले की तुलना में बहुत अधिक थी और इस प्रकार के अनभिप्रेत मिश्रण को टाला जाना चाहिए था।

कोयले का उपभोग

- यद्यपि स्टेशनों कावार्षिक औसत विशिष्ट कोयला उपभोग (एससीसी) 1 कि.ग्रा प्रति यूनिट विद्युत से कम रहा, लेखापरीक्षा ने इसमें महत्वपूर्ण मासिक अन्तर पाए। अधिकतम एससीसी मौदा और बदरपुर स्टेशनों में सबसेअधिक पाया गया।
- एक यूनिट ऊर्जा के उत्पादन मे कोयले की खपत में आयातित कोयले के मिश्रण के कम या ज्यादा होने से कोई अंतर नहीं आया। इससे संदेह उठता है कि आयातित कोयला वास्तव में स्वदेशी कोयले से बेहतर था अथवा नहीं, जबकि एनटीपीसी ने आयातित कोयले की खरीद मेंउच्चतर लागत का व्यय किया था।